Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item which appeared in the Hindustan Times dated the 7th January, 1988 wherein it has been stated that heroin worth crores of rupees was seized in Ludhiana, Punjab;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether any arrests have been made in this connection;

(d) the estimated value of heroin seized in the country during the past six months, particularly in Delhi, Haryana and Punjab; and

(e) what steps Government have taken to curb such activities?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF REVENUE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI AJIT PANJA): (a) to (e) On 6-1-1988, the Customs staff at Ludhiana seized 175 kgs. of brownish powder, reported to be heroin, and 39 kgs. of opium along with two trucks involved in the case. Four persons arrested in this connection have been remanded to judicial custody.

No precise value of the drugs seized can be estimated as this is dependent upon various factors like quality of the drugs, place of origin, etc.

Government have initiated various aggressive counter-measures against drug-trafficking which include strengthening of the preventive and intelligence machinery, adoption of a liberalised reward scheme for officers and informers, increased co-operation between various drug law enforcement agencies, bilateral co-operation with Pakistan and regional co-operation under the umbrella of SAARC. The matter is also kept under constant review for appropriate action.

पूरी होने के लिए लम्बित सिंचाई परियोजनाएं

2108. **डा. रत्नाकर पाण्डेय** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सिंचाई परियोजनाओं के राज्यवार नाम क्या-क्या हैं जो अपने पूरा होने की निर्धारित अवधि से पीछे हैं ;

(ख) मूलत: इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना थी ;

(ग) संशोधित कार्यक्रम के अनुसार इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है ; और

(घ) उन पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार 181 वृहद् तथा 433 मध्यम निर्माणाधीन परियोजनाएं सामान्यतया पूरा होने की निर्धारित अवधि से पीछे हैं । परियोजना रिपोर्टों में पूरा किए जाने की दी गई संभावित तारीखें अन्तरिम होती हैं तथा उनका पूरा होना राज्यों द्वारा दी गई पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है । सातवीं योजना के आरंभ में निर्माणाधीन वृहद तथा मध्यम परियोजनाओं की आगे लाई गई लागत लगभग 26,600 करोड़ रुपए होने का अनुमान था ।

बाण सागर परियोजना

2109. **डा. रत्नाकर पाण्डेय** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाण सागर परियोजना से उत्तर प्रदेश को कब से लाभ मिलना शुरू होने की संभावना है ;

(ख) इस समय यह परियोजना किस चरण में है ; और